

भारत



भारत के अधिकांश वरिष्ठ कारोबारी अधिकारी (84%) मानते हैं कि देश को 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शफिट करना चाहिए। यह सोच 2047 तक वकिसति भारत के लक्ष्य को पाने के सरकारी एजेंडे से मेल खाती है।

लगातार आई सरकारों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को भारत के लिए टिकाऊ आर्थिक विकास का आधार बनाने की दशा में उठाए गए कदमों को, लगभग सभी बज़िनेस लीडर्स का समर्थन मिला है। 99% भारतीय कंपनियों के उच्च अधिकारी इस पक्ष में हैं कि देश को जीवाश्म ईंधनों से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बजिली उत्पादन की ओर बढ़ना चाहिए। इनमें से ज्यादातर (84%) चाहते हैं कि यह बदलाव अगले 10 सालों के भीतर हो।

इसके लिए ज़रूरी होगा कि राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की हसिसेदारी तेज़ी से बढ़ाई जाए। अभी देश की 75% बजिली जीवाश्म ईंधनों (ज्यादातर कोयले, जो 72% है) से बनती है।¹ हालांकि, दशा सही है। हाल के वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है, और अब इसकी हसिसेदारी कुल बजिली उत्पादन में 23% तक पहुँच गई है।² यह बढ़त खासतौर पर सौर ऊर्जा क्षेत्र में देखि रही है—सरिफ 2024 में भारत ने 24.5 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे बड़ी सालाना वृद्धि है।³

यह रुझान इस बात पर जोर देता है कि देश की बजिली वतिरण कंपनियों को 2030 तक अपनी

आपूर्तिका 44% हसिसा नवीकरणीय स्रोतों से सुनिश्चिति करना होगा।⁴

नीतगित प्राथमकितार्एँ

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बजिली को बढ़ावा देने के लिए, 68% बज़िनेस अधिकारी चाहते हैं कि भारत सीधे रनियूएबल एनर्जी ससिटम को अपनाए और बीच के चरण के तौर पर जीवाश्म ईंधनों पर नरिभर न रहे। पाँच में से तीन (59%) अधिकारियों का मानना है कि यह मॉडल सरकार के तीन बड़े लक्ष्यों— ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करना, आर्थिक वृद्धिको गता देना, और हर नागरिक को ससूती व भरोसेमंद बजिली देना—से बेहतर मेल खाता है।

वर्तमान में जीवाश्म गैस से सरिफ 2.6% बजिली बनती है, और इसमें वसितार की योजनाएँ भी सीमति हैं।⁵ लेकिन कोयले में नविश रोकने के फ़ैसले अभी धीमी गति से लागू हो रहे हैं।⁶ भारत उन कुछ G20 देशों में शामिल है जो अब भी नई कोयला क्षमता में नविश कर रहे हैं। ऐसा ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने और बजिली की कीमतें कम रखने के लिए किया जा रहा है।⁷

1 <https://www.iea.org/countries/india/energy-mix>

2 https://cea.nic.in/wp-content/uploads/installed/2025/01/IC_Jan_2025_allocation_wise.pdf

3 <https://www.powerengineeringint.com/solar/india-adds-a-record-24-5gw-of-solar-power-capacity-in-2024/>; https://cea.nic.in/wp-content/uploads/resd/2024/12/Broad_Overview_of_RE_Generation_Dec_2024.pdf

4 सरकार ने नवीकरणीय स्रोतों से खरीद के दायित्व के साथ-साथ अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ भी लागू की हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, नवीकरणीय उत्पादन दायित्व और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएँ। <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/india-will-require-discos-source-43-their-supply-renewables-2030.html>; <https://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/india/assets/pdfs/achieving-500-gw-of-re-capacity-by-2030.pdf>

5 <https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/>

6 2023 राष्ट्रीय वदियुत योजना में कोयला-आधारित वदियुत को 2031-2032 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता के 33% तक घटा लाने का लक्ष्य है। COP 27 में सरकार ने सामान्य जीवाश्म-ईंधन चरणबद्ध समापत (यानी केवल कोयला नहीं) के लिए भी अपने समर्थन का संकेत दिया था। तब तक, भारत इस तर्क पर अडगि था कि उत्तर के औद्योगिक देशों को कार्बन-मुक्त की अगुवाई करनी चाहिए।

7 जनवरी 2025 में लगभग 30 गीगावाट की नई कोयला क्षमता नरिमाणधीन थी, तथा 81.44 गीगावाट नरिमाण-पूर्व वकिस के चरण में थी। <https://globalenergymonitor.org/projects/global-coal-plant-tracker/summary-tables/> [Coal plants by country (MW)]

हालांकि, बजिनेस लीडर अब चाहते हैं कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा में नविश को प्राथमिकता दे। इनमें से 93% अधिकारी 2035 तक कोयले का इसतेमाल चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के पक्ष में हैं।

हाल की फ़र्म एंड डिसिपैचेबल रनियूएबल एनर्जी परियोजनाओं की नविदाएँ दिखाती हैं कि स्टोरेज-आधारित रनियूएबल पावर की लागत अब नई कोयला परियोजनाओं के बराबर है।⁸ इसका मतलब है कि यह विकल्प व्यवहार्य भी है और टिकाऊ भी। अगर भारत को जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और अनश्चितता के चक्र से बाहर निकलना है, तो कोयले में नए नविश पर रोक लगानी ही होगी।

साथ ही, पुराने और कम कुशल कोयला बजिली संयंत्रों को बंद करना सस्टिम की क्षमता को बेहतर कर सकता है।⁹ सरकार और नजी क्षेत्र, दोनों की स्थिर और भरोसेमंद बजिली की ज़रूरत को देखते हुए, स्टोरेज और ग्रिड ढांचे को मज़बूत करने के लिए तेज़ नविश की आवश्यकता है।

वदियुत नीति

44% बजिनेस अधिकारी चाहते हैं कि सरकार अपनी जलवायु योजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका को लेकर ज्यादा स्पष्टता दे।

2014 से सत्ता में रही मोदी सरकार ने पब्लिक मंचों पर लगातार स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन किया है। 2019 में सरकार ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 450 गीगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा था।¹⁰ अब यह लक्ष्य वकिसति भारत @2047 नीति के तहत बढ़ाकर 2040 तक 900 गीगावाट

और 2047 तक 1,500 गीगावाट कर दिया गया है।¹¹ इसके साथ, भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है।¹²

इस सर्वे में 84% बजिनेस अधिकारी चाहते हैं कि भारत 2035 तक पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शफिट कर जाए। साथ ही, 44% यह भी चाहते हैं कि जलवायु नीति में रनियूएबल एनर्जी की भूमिका को और स्पष्ट किया जाए।

बजिनेस सेक्टर की अपेक्षाएँ

बजिनेस सेक्टर के पास नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के पक्ष में कई ठोस कारण हैं। सबसे बड़ा तर्क है—इनकी लागत में गिरावट। इससे संचालन खर्च घट सकता है और भारत की इंडस्ट्री व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रतस्पर्धा क्षमता बढ़ सकती है।

लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। लगभग 45% बजिनेस प्रमुखों को नई रनियूएबल परियोजनाओं के लिए फंडिंग को लेकर चिंता है। 49% अधिकारियों को लगता है कि अग्रिमि लागत एक बड़ी रुकावट है।¹³

इसका समाधान यह हो सकता है कि सरकार स्पष्ट रणनीतियाँ बनाए और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अनिवार्य रूप से नवीकरणीय स्रोतों से बजिली खरीदने के निर्देश दे—खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ बदलाव की सबसे ज्यादा ज़रूरत है।

सर्वे में शामिल 51% अधिकारी यह भी चाहते हैं कि कोयले पर निर्भर राज्यों में कर्मचारियों को नए स्किल्स सिखाए जाएँ और जो पहले से रनियूएबल सेक्टर में हैं, उनके कौशल और मज़बूत किए जाएँ।

आपके देश के लिए जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव के शीर्ष लाभ (प्रतशित जनता जिन्होंने नमिनलखिति चुना)

राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि

○ 59%

सभी के लिए बजिली उपलब्धता

○ 59%

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार

○ 56%

8 <https://ember-energy.org/latest-updates/navigating-risks-to-unlock-indias-500-gw-renewable-energy-target-by-2030/>

9 <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/discoms-prefer-new-age-re-tenders-over-plain-vanilla-solar-wind-experts/109275655>

10 https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pms-remarks-at-climate-action-summit-2019-during-74th-session-of-unga/

11 <https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2024/04/Viksit-Bharat@2047-A-Blueprint-of-Micro-and-Macro-Economic-Dynamics.pdf>

12 <https://climateactiontracker.org/countries/india/net-zero-targets/>

13 भारत को ऊर्जा स्रोत बदलाव के लिए ही 2050 तक हर वर्ष 60,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नविश करना होगा। शुरुआती वर्षों में अधिक नविश किया जाए तो यह आँकड़ा 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। <https://fsr.eui.eu/looking-at-the-costs-of-the-energy-transition-from-an-indian-perspective/>